भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 716

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।

02 श्रावण, 1948 (शक)

डिजिटल क्षेत्र में बाहरी मॉडलों पर निर्भरता

716. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सूचकांक में भारत को 71वां स्थान प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि डिजिटल क्षेत्र में भारत कंप्यूटर पावर चिप, क्लाउड सेवाओं और मॉडलों के लिए अन्य देशों पर निर्भर है; और

(घ) भारत डिजिटल क्षेत्र में बाहरी मॉडलों पर कितना निर्भर है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (घ): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एआई तैयारी सूचकांक नीति निर्माताओं को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मार्गदर्शन करने के लिए विकसित किया गया एक सांकेतिक उपाय है, न कि रैंकिंग उद्देश्यों के लिए।

एआई तैयारी सूचकांक 4 प्रमुख आयामों का योग है: डिजिटल बुनियादी ढांचा, नवाचार और आर्थिक एकीकरण, मानव पूंजी और श्रम बाजार नीतियां और विनियमन और नैतिकता।

भारत ने 0.49 का संचयी स्कोर हासिल किया है और यह 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। इंडियाएआई मिशन की मंजूरी और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के पारित होने के साथ, भारत का एआई तैयारी सूचकांक बहुत अधिक होने की संभावना है।

तब से, भारत ने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रिपोर्ट 2025 एआई प्रतिस्पर्धात्मकता और इकोसिस्टम जीवंतता में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान देती है। स्टैनफोर्ड एचएआई इंडेक्स 2026 के अनुसार, भारत एआई कौशल प्रवेश में दुनिया में सबसे आगे है।

<u>इंडियाएआई मिशन:</u>

भारत की एआई नीति प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य इससे जुड़े जोखिमों को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार पैदा करना है।

भारत की एआई रणनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख मजबूत कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है। इंडिया एआई मिशन एआई मॉडल, एप्लिकेशन, डेटासेट, प्रतिभा विकास और सस्ती गणना के विकास सहित सात स्तंभों के तहत भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है।

सरकार ने निम्नानुसार पर्याप्त स्वदेशी क्षमता का निर्माण किया है -

एआई मॉडल:

भारत सरकार बड़े भाषा मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय स्टार्टअप और संस्थानों का समर्थन कर रही है।

समर्थन के लिए 20 स्वदेशी सॉवरेन मॉडल प्रस्तावों की पहचान की गई है, जिसमें 12 एलएलएम और 8 एसएलएम शामिल हैं। अब तक की उल्लेखनीय सफलताओं में शामिल हैं:

- सर्वम एआई का सर्वम 30 बिलियन पैरामीटर और 105 बिलियन पैरामीटर मॉडल
- Gnani.AI का स्पीच-टू-स्पीच मॉडल
- भारतजेन के बहुभाषी फाउंडेशन मॉडल
- अवतार एआई का वीडियो जनरेशन मॉडल

डोमेन-विशिष्ट एसएलएम में स्वास्थ्य सेवा, भाषा प्रौद्योगिकियों और एजेंट एआई सिस्टम को संबोधित करने वाले विशेष मॉडल और एआई फ्रेमवर्क शामिल हैं, जो विकास और तैनाती के विभिन्न चरणों में हैं।

सस्ती गणना:

- गणना सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया गया: 15
- समर्थित परियोजनाओं की संख्या: 237
- जीपीयू घंटे स्वीकृत: 93.18 लाख जीपीयू घंटे

अनुप्रयोग विकास:

- 12 राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन/नवाचार चुनौतियां शुरू की गईं।
- 62 एआई प्रोटोटाइप और 20 एआई समाधान परिनियोजन के विकास का समर्थन किया

प्रतिभा विकास:

- 178 संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में 686 फैलोशिप प्रदान की गई हैं।
- सभी के लिए युवा एआई कार्यक्रम को 26.5 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा पूरा किया गया है।

इंडियाएआई प्रयोगशालाएं:

- 27 इंडिया डेटा और एआई प्रयोगशालाएं स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने 2500 से अधिक छात्रों के लिए प्रशिक्षण का समर्थन किया है।
- अतिरिक्त 188 प्रयोगशालाओं पर काम चल रहा है।

डेटासेट:

एआईकोष प्लेटफ़ॉर्म 329 एआई मॉडल, 35 टूलकिट और 202 प्रलेखित उपयोग के मामलों को होस्ट करता है।

एआई उत्कृष्टता केंद्र:

सरकार ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उद्योग भागीदारों के सहयोग से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एआई-सीओई) की स्थापना के लिए एक योजना को भी मंजूरी दी है।

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम

सरकार सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और सेमीकॉन 2.0 के माध्यम से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी मजबूत कर रही है। सेमीकॉन 1.0 के तहत, 12 स्वीकृत संयंत्रों में से 3 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। चिप्स का उपयोग भारत में होने के साथ-साथ निर्यात भी किया जा रहा है। 2028 तक, टाटा धोलेरा फैब भी चालू हो जाएगा।

सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, जर्मनी और नीदरलैंड सहित देशों के साथ साझेदारी और पैक्स सिलिका में भागीदारी के माध्यम से विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण भी कर रही है।

कुल मिलाकर, सरकार का दृष्टिकोण पूरे एआई स्टैक में संप्रभु क्षमताओं का निर्माण करना है जिसमें मॉडल, एप्लिकेशन, कंप्यूट, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और प्रतिभा शामिल हैं।

*****